

मुकदमों का विवरण

शीओ राज सिंह (निर्णय) एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. के माध्यम से।

भारत संघ और ए. एन. आर. (2015 की सिविल अपील संख्या 5867) अक्टूबर 09, 2023

[बेला एम. त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय को अपील की प्रस्तुति में देरी को माफ करने में न्यायसंगत ठहराया गया था; और क्या विभाग ने पर्याप्त कारण दिखाया था जिसके लिए अपील को सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था।

विलंब/विलंब-विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग-उच्च न्यायालय ने संदर्भ न्यायालय के निर्णय से विभाग द्वारा अपील प्रस्तुत करने में लगभग **479** दिनों की देरी को माफ कर दिया, जिसके तहत उसने भूमि मालिकों को देय मुआवजे में वृद्धि की थी।

आयोजित किया गया: निजी पक्षों और राज्य के पर्याप्त अधिकार केवल देरी के तकनीकी विचारों के कारण सीमा पर पराजित नहीं होते हैं-हालांकि, अदालतों के लिए उपलब्ध एक विवेकाधीन शक्ति होने के नाते देरी की माफी, विवेकाधिकार का प्रयोग आवश्यक रूप से दिखाए गए कारण की पर्याप्तता और स्पष्टीकरण की स्वीकार्यता की डिग्री पर निर्भर करना चाहिए, देरी की अवधि मायने नहीं रखती है-ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो सभी स्थितियों को पूरा करता है-कभी-कभी, पर्याप्त कारण दिखाए जाने या स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव के कारण, कम से कम अवधि की देरी को माफ नहीं किया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य मामलों में, स्पष्टीकरण संतोषजनक और स्वीकार्य होने पर लंबी अवधि की देरी को माफ किया जा सकता है-अदालतों को 'स्पष्टीकरण' और 'बहाने' के बीच अंतर करना चाहिए।

743

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में विभाग की असमर्थता, उसमें दिए गए कारणों के लिए, हस्तक्षेप की गारंटी देने वाली किसी भी त्रुटि के लिए पर्याप्त नहीं है-विवेक का प्रयोग, कभी-कभी, अदालतों द्वारा एक उदार और न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण की मांग करता है, जहां राज्य को कुछ छूट प्रदान की जा सकती है-गुप्त ताकतें जो राज्य द्वारा अपील को निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने से रोकने के लिए काम कर रही हैं ताकि उच्च न्यायालय को निचली अदालत के आदेश की वैधता और वैधता पर निर्णय लेने की अनुमति न दी जा सके और इस तरह अपवित्र लाभ प्राप्त किए जा सकें, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है-सरकारी कार्यों की भव्य योजना के कामकाज में

बाधाओं को प्रतिस्पर्धी हितों के संतुलन पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर दूर करना होगा-इस प्रकार, विवादित आदेश[पैरा 29,30,32,37,38]

विलम्ब/विलंब-विलम्ब के लिए एक 'स्पष्टीकरण' और एक 'बहाना'-के बीच अंतर:

आयोजित किया गया:अदालतों को एक 'स्पष्टीकरण' और एक 'बहाने' के बीच अंतर करना चाहिए-स्पष्टीकरण को बहाने से अलग करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए-एक 'स्पष्टीकरण' किसी को सभी तथ्य देने और किसी चीज का कारण निर्धारित करने के लिए बनाया गया है-यह किसी विशेष घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में मदद करता है और व्यक्ति को यह इंगित करने की अनुमति देता है कि जो कुछ हुआ है वह उसकी गलती नहीं है, अगर यह वास्तव में उसकी गलती नहीं है-एक 'बहाना' अक्सर एक व्यक्ति द्वारा हमले के दौरान जिम्मेदारी और परिणामों से इनकार करने के लिए कहा जाता है।

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

बलवंत सिंह (मृत) बनाम जगदीश सिंह और अन्य। (2010) 8 एससीसी 685:[2010] 8 एस. सी. आर. 597; दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम भारत संघ और अन्य।

(2020) 13 एससीसी 745:[2019] 16 एससीआर 1259; कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण,

अनंतनाग और एन. आर. वी.एमएस. काटीजी और ओआरएस। (1987) 2 एससीसी 107:[1987] 2 एस. सी. आर. 387; नागालैंड राज्य बनाम लिपोक एओ और अन्य। (2005) 3 एससीसी 752:[2005] 3 एस. सी. आर. 108; लंका वेंकटेश्वरलु (मृत) बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और

ओआरएस। (2011) 4 एससीसी 363:[2011] 3 एससीआर 217; पोस्टमास्टर जनरल और अन्य।

v. लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और एनआर। (2012) 3 एससीसी 563:[2012] 1 एससीआर 1045; ईशा भट्टाचार्य बनाम रघुनाथपुर की प्रबंध समिति

नफ़र अकादमी और अन्य। (2013) 12 एससीसी 649:[2013] 9 एस. सी. आर. 782; 745 का राज्य

शीओ राज सिंह (निर्णय) एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. के माध्यम से।भारत संघ और ए. एन. आर.

मणिपुर और ओआरएस. वी.कोटिंग लमकांग (2019) 10 एससीसी 408:[2019] 13 एससीआर

565; जी. रामगौड़ा बनाम विशेष। भूमि अधिग्रहण कार्यालय (1988) 2 एस. सी. सी. 142: [1988] 3 एस. सी. आर. 198; हरियाणा राज्य बनाम चंद्र मणि (1996) 3 एस. सी. सी. 132:[1996] 1 एससीआर 1060; विशेष तहसीलदार, भूमि अधिग्रहण बनाम के. वी.

आयसुम (1996) 10 एस. सी. सी. 634:[1996] 3 पूरक।एस. सी. आर. 848; मंजुनाथ आनंदप्पा बनाम तमन्नासा (2003) 10 एस. सी. सी. 390:[2003] 2 एससीआर 1068;

गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा (1980)

2 एससीसी 593:[1980] 2 एस. सी. आर. 146; एम. पी. बनाम राज्यभेरूलाल (2020) 10 एस. सी. सी. 654:[2020] 8 एस. सी. आर. 912-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2015 की सिविल अपील सं. 5867/2010 के एल. ए. ए. No.655 और 2010 के सी. एम. No.11018 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 21.12.2011 निर्णय और आदेश से।

रूप:

चिनमय प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री दिव्या ज्योति सिंह, सुल्तान चौधरी, सुश्री शोभा गुप्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

संजीव सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मालविका कपिला कालरा, सुश्री अंजलि सिंह, सुश्री राधा गुप्ता, भावेश शर्मा, तनवंगी शुक्ला, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, जे।

चुनौती

1. यह अपील, कुछ प्रभावित भूमि मालिकों के कहने पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ("उच्च न्यायालय", इसके बाद) के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 21 दिसंबर 2011 के आदेश को चुनौती देती है। चुनौती के तहत आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सीमा अधिनियम, 1963 ("सीमा अधिनियम", इसके बाद) की धारा 5 के तहत भारत संघ ("प्रथम प्रतिवादी", इसके बाद) द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया और इस तरह अपील की प्रस्तुति में लगभग 479 दिनों की देरी को माफ कर दिया।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत संदर्भ न्यायालय के निर्णय से।

मुद्दा

2. जिस सीमित मुद्दे पर हमें निर्णय लेने का काम सौंपा गया है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय को अपील की प्रस्तुति में देरी को माफ करने में न्यायसंगत ठहराया गया था। इस प्रक्रिया में, हमें आवश्यक रूप से इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या प्रथम प्रतिवादी ने पर्याप्त कारण दिखाया था जिसके लिए अपील को सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

आवेदन को बढ़ावा देने वाले प्रासंगिक तथ्य

3. इस अपील की उत्पत्ति भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में हुई है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से यह देखा गया है कि एल. ए. सी. सं. 198/08 में संदर्भ न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2008 के अपने आदेश के अनुसार भूमि मालिकों को देय मुआवजे में वृद्धि की है। इस तरह के आदेश को प्रथम प्रतिवादी द्वारा 2 जून 2010 को उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील में चुनौती देने की मांग की गई थी, जिसकी संख्या एल. ए. थी। ऐप. नं. 655/2010। चूंकि अपील पर समय की पाबंदी थी (479 दिनों की देरी), इसलिए प्रथम प्रतिवादी ने देरी को माफ करने के लिए आवेदन किया। 4. अभिवचनों के साथ-साथ अभिलेख पर अन्य सामग्रियों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय को संतुष्ट किया गया कि प्रथम प्रतिवादी ने, अपीलार्थी के रूप में, पर्याप्त कारण दिखाया था जिसके लिए वह समय के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता था। इसलिए, विवादित आदेश के अनुसार, यह सी. एम. संख्या 11018/2010 की अनुमति देने के लिए आगे बढ़ा। अपील की प्रस्तुति में 479 दिनों की देरी को माफ कर दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा 2 करोड़ रुपये की लागत लगाए बिना नहीं। प्रथम उत्तरदाता पर 10,000/-।

5. प्रथम प्रतिवादी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, जिसे अंततः उच्च न्यायालय का समर्थन मिला, खेदजनक संस्थागत अक्षमता और निंदनीय नौकरशाही जड़ता को प्रकट करता है।

6. संदर्भ न्यायालय के आदेश के बाद की निम्नलिखित घटनाओं का संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। संदर्भ न्यायालय के समक्ष प्रथम प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने 31 अक्टूबर 2008 को पारित किए जाने के बावजूद 22 अप्रैल 2009 को संदर्भ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन किया। इसके बाद, 30 जुलाई 2009 को प्रमाण पत्र की संशोधित प्रति प्राप्त हुई। 10 अगस्त 2009 को, उप कानूनी सलाहकार (भूमि और भवन) ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए प्रथम प्रतिवादी को सलाह दी। द 747

शीओ राज सिंह (निर्णय) एलआरएस के माध्यम से।

प्रधान सचिव (भूमि और भवन) ने 11 अगस्त 2009 को अपील दायर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी (उच्च न्यायालय के समक्ष माफी में देरी के लिए आवेदन में गलती से 2010 के रूप में उल्लेख किया गया है)। इसके बाद उप कानूनी सलाहकार (भूमि और भवन) ने 26 अगस्त 2009 को उपायुक्त (पूर्व) को प्रमाण पत्र और प्रधान सचिव की मंजूरी भेजी, जो 28 अगस्त 2009 को प्राप्त हुई, जिसके बाद मामला 31 अगस्त 2009 को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास पहुंचा। इसके बाद मामले को 17 सितंबर 2009 को अपील तैयार करने के लिए प्रथम प्रतिवादी के वकील को भेजा गया और इसे 7 अक्टूबर 2009 को प्रथम प्रतिवादी को वापस भेज दिया गया। रुपये के आवश्यक अदालत शुल्क के भुगतान के लिए शुल्क। 51,36,592-12 अक्टूबर 2009 को संबंधित उपायुक्त के समक्ष रखा गया था। इसके बाद 15 दिसंबर 2009 को इसके लिए बजट को मंजूरी दी गई। इस बीच, संदर्भ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति गलत जगह पर रखी गई थी, जिसके लिए एक और आवेदन की आवश्यकता थी जो 24 अक्टूबर 2009 को किया गया था। इसके अनुसार, प्रमाण पत्र की प्रति 3 नवंबर 2009 को प्राप्त हुई थी; इसके बाद लेखा विभाग ने 12 जनवरी 2010 को आवश्यक धन के लिए मामले को वित्त विभाग को भेजा। लेखा विभाग को धन को मंजूरी देने वाला वित्त विभाग का 15 मार्च 2010 का पत्र 25 मार्च 2010 को प्राप्त हुआ था। अदालती शुल्क के लिए चेक अप्रैल 2010 में प्राप्त हुआ था, जिसके बाद इसे 7 मई 2010 को कोषागार में जमा किया गया था। कोषागार ने 11 मई 2010 को अदालत की फीस जमा की थी, जिसके बाद 2 जून 2010 को अपील दायर की गई थी।

एप्पेल्लान्ट की सामग्री

7. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चिनमॉय प्रदीप शर्मा ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने पर्याप्त कारण बताए बिना देरी को माफ करने में स्पष्ट रूप से गलती की। उन्होंने बताया कि उद्धृत कारण किसी भी उपाय से उचित नहीं थे, और देरी को माफ करने के लिए ऐसे भूमि अधिग्रहण मामलों में दिए गए अस्वीकार्य स्पष्टीकरण आदतन थे। देरी को माफ करने के अनुरोध को मंजूरी देने वाले आदेश को स्वीकार करते हुए, यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने कई अवसरों पर कम अवधि की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया था। हम पर यह प्रभाव डालने का प्रयास किया गया कि यह प्रथम प्रतिवादी का मामला भी नहीं था कि वर्तमान मामले में उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अधिक ठोस था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

कई मंचों के समक्ष अन्य मामलों की तुलना में जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया था। उन्होंने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय इस अंतर-विभागीय पत्राचार की सराहना नहीं करने में न्याय की विफलता का कारण बना, जो देरी को समझाने के प्रयास से रहित है, इसे पर्याप्त कारण दिखाने के बराबर नहीं है। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की यांत्रिक और विकृत के रूप में आलोचना की गई थी।

8. श्री शर्मा ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष देरी को माफ करने के लिए आवेदन में केवल संदर्भ न्यायालय के आदेश के बाद 'मामलों की श्रृंखला' का वर्णन प्रदान किया गया है। वर्तमान मामले में, न केवल संदर्भ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन करने में लगभग 6 महीने की देरी हुई थी, बल्कि 11 अगस्त 2009 को प्रधान सचिव (भूमि और भवन) से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अपील करने में 10 महीने की देरी भी हुई थी। श्री शर्मा ने आग्रह किया कि इस तरह के स्पष्टीकरण को बलवंत सिंह के अनुसार संतोषजनक रूप से समझाई गई देरी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

(मृत) बनाम जगदीश सिंह और अन्य। 1.

9. इस न्यायालय के कई अन्य फैसलों पर निर्भर करते हुए, विशेष रूप से

दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम भारत संघ और अन्य 2, श्री शर्मा में निर्णय

प्रार्थना की कि विवादित आदेश को दरकिनार करके और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम प्रतिवादी की अपील को समय की पाबंदी के रूप में खारिज करके अपील की अनुमति दी जाए।

जिम्मेदारियों की सामग्री

10. इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजीव सेन ने इस न्यायालय से आग्रह किया कि वह विवादित आदेश में हस्तक्षेप न करे क्योंकि उच्च न्यायालय ने विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए, अपील की प्रस्तुति में देरी के कारणों की पर्याप्तता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद देरी को माफ कर दिया था। 11. श्री सेन को हमें संदर्भ न्यायालय के समक्ष प्रथम प्रतिवादी के वकील के लापरवाहीपूर्ण आचरण के बारे में सूचित करते हुए सुना गया था, जिससे उन्हें सूची में शामिल किया गया था। उनके अनुसार, संदर्भ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन करने में देरी मुख्य रूप से संबंधित वकील के गैर-पेशेवर आचरण के कारण हुई थी और इसलिए श्री सेन ने अनुरोध किया कि इस तरह के आचरण का अदालत के दिमाग में कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।

1 (2010) 8 एससीसी 685। 2 (2020) 13 एससीसी 745।

शीओ राज सिंह (निर्णय) एलआरएस के माध्यम से।

749

& ओआरएस। V. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपांकर दत्त, जे.] 750

शुरुआत में ही प्रथम प्रत्यर्थी का दावा, विशेष रूप से जब दांव अधिक होते हैं और यदि विवादित आदेश को रोक दिया जाता है तो सरकारी खजाने के अनावश्यक रूप से समाप्त होने की संभावना होती है।

12. जहां तक बाद की देरी का संबंध है, श्री सेन ने हमें सरकारी विभागों की अवैयक्तिक मशीनरी और नौकरशाही कार्यप्रणाली की याद दिलाने की कोशिश की जो इस तरह की देरी में योगदान देती

है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की देरी अक्सर समुदाय के लिए राज्य के सामूहिक उद्देश्य के रास्ते में बाधा के रूप में कार्य करती है, जहां अंतिम शिकार जनहित होता है।

13. श्री सेन ने यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार का उचित प्रयोग करते हुए व्यावहारिक मार्ग चुना था, यह देखते हुए कि अपील को आगे बढ़ाने में लापरवाही लापरवाही के बराबर नहीं थी; इसी आलोक में उच्च न्यायालय ने प्रथम प्रतिवादी पर भारी लागत लगाने के बाद देरी को माफ कर दिया था।

14. पूर्वगामी प्रस्तुतियों के आलोक में, श्री सेन ने प्रार्थना की कि उच्च न्यायालय को एल. ए. पर निर्णय लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। ऐप. नहीं. 655/2010 अपने गुण-दोष पर जहां अपीलार्थी के पास उच्च न्यायालय को अपील को खारिज करने के लिए मनाने का अवसर होगा, यदि बिल्कुल भी हो। अतः उन्होंने प्रार्थना की कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

भविष्यवाणियाँ

15. दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिन पर हम आगे विचार करने का प्रस्ताव करते हैं।

16. कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग और अन्न बनाम। एमएस. काटीजी

& ओआरएस। 3 संबंधित उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण मामले में कलेक्टर द्वारा अपील प्रस्तुत करने में 4 (चार) दिनों की देरी को माफ नहीं किया, जिसके लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन को खारिज करने का आदेश अपील में लिया गया था। इस न्यायालय ने राय दी कि विधायिका ने धारा 5 के तहत शक्ति प्रदान की थी ताकि अदालतें "गुण-दोष" के आधार पर मामलों का निपटारा करके पक्षों के साथ पर्याप्त न्याय कर सकें। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि विधायिका द्वारा प्रयुक्त "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति अदालतों को कानून को सार्थक तरीके से लागू करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से लोचदार है जो न्याय के उद्देश्यों को कम करता है-जो कि अस्तित्व के लिए जीवन-उद्देश्य है।

3 (1987) 2 एससीसी 107।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

न्यायालयों की संस्था। ऐसे मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाने के बावजूद, जिसे न्यायसंगत कहा गया था, इस न्यायालय ने अफसोस व्यक्त किया कि यह संदेश पदानुक्रम में अन्य सभी न्यायालयों तक नहीं पहुंचा है और तदनुसार, न्यायालयों को उदार और न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया था। निर्णय का निम्नलिखित अंश इस न्यायालय के इस अहसास को दर्शाता है कि:

“3. [...] और इस तरह का एक उदार दृष्टिकोण सिद्धांत रूप में अपनाया जाता है क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि:

4. जब एक दूसरे के खिलाफ पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचार रखे जाते हैं, तो पर्याप्त न्याय के कारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि दूसरा पक्ष गैर-जानबूझकर देरी के कारण किए जा रहे अन्याय में निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है।

6. यह समझना चाहिए कि न्यायपालिका का सम्मान तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की अपनी शक्ति के कारण नहीं किया जाता है, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अन्याय को दूर करने में सक्षम है और ऐसा करने की उम्मीद की जाती है।”

(मूल में बोल्ड)

17. नागालैंड राज्य बनाम लिपोक एओ और अन्य। **4** एक अपील से उभरा

जहां इस न्यायालय ने कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए अनुमति देने के लिए आवेदन करने में राज्य की 57 दिनों की देरी को माफ कर दिया। इस न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां एक-दूसरे के खिलाफ पर्याप्त न्याय और एक तकनीकी दृष्टिकोण रखा गया था, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिसमें पहले वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, इस न्यायालय ने नोट किया कि जो गिना गया वह वास्तव में देरी के कारण की पर्याप्तता थी, न कि लंबाई, जहां देरी की कमी को स्वीकार करने के लिए असाधारण विवेक का उपयोग करते समय माना जाएगा। इस न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि अदालतों को किसी मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर तय करने का प्रयास करना चाहिए, जब तक कि वह निराशाजनक रूप से बिना गुण-दोष के न हो। इसमें यह भी देखा गया कि राज्य को एक व्यक्ति के समान आधार पर रखना अनुचित होगा क्योंकि यह एक अवैयक्तिक तंत्र था जो अपने अधिकारियों के माध्यम से काम कर रहा था।

4 (2005) 3 एससीसी 752।

शीओ राज सिंह (निर्णय) एलआरएस के माध्यम से।

751

& ओआरएस। V. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपांकर दत्त, जे.] 752

18. बलवंत सिंह (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXII नियम 9 के तहत एक आवेदन के माध्यम से याचिकाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने में 778 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया। यह देखा गया कि यद्यपि पर्याप्त कारण को उदार तरीके से समझा जाना चाहिए, लेकिन इसे दूसरे पक्ष के साथ अन्याय करने के बराबर नहीं माना जा सकता है। उदार व्यवहार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कारण के लिए, यह उचित समय के भीतर और संबंधित पक्ष के उचित आचरण के माध्यम से होना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि क्षमा के लिए इस तरह के आवेदन को सकारात्मक रूप से देखने के लिए,

यह सही और प्रशंसनीय स्पष्टीकरणों पर आधारित होना चाहिए, और एक सामान्य विवेकपूर्ण व्यक्ति के सामान्य आचरण को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसके अलावा, समझाई गई देरी को स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए ताकि अत्यधिक अस्पष्टीकृत देरी से माफी मिल सके।

19. लंका वेंकटेश्वरलु (मृत) बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

& ओआरएस। 5 एक ऐसा मामला हुआ जहां इस न्यायालय ने संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने की याचिका में 883 दिनों की देरी दोनों को माफ करते हुए विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया, साथ ही प्रत्यर्थियों द्वारा अपीलार्थी के कानूनी प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लाने में 3703 दिनों की देरी के साथ। इस न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने संबंधित सरकारी वकीलों को उसके समक्ष अपील पर मुकदमा चलाने में उनकी लापरवाही और देरी के लिए पर्याप्त कारण प्रदान नहीं करने के लिए फटकार लगाई, फिर भी उसने देरी को अनुचित ठहराने के बावजूद इसे माफ कर दिया।

20. पोस्टमास्टर जनरल एंड ओआरएस. वी.लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड

& एन. आर. 6, इस न्यायालय ने नोट किया कि ऐसे मामलों में जब कोई घोर लापरवाही, जानबूझकर निष्क्रियता, या निष्पक्षता की कमी नहीं थी, तो पर्याप्त न्याय प्रदान करने के लिए एक उदार रियायत अपनाई जानी चाहिए, लेकिन न्यायालय के समक्ष तथ्यों पर, अपीलार्थी इस न्यायालय के पहले के फैसलों का लाभ नहीं उठा सकता था। इसके अलावा, केवल इसलिए कि राज्य शामिल था, देरी को माफ करने के लिए कोई अलग मीट्रिक लागू नहीं किया जा सकता था। महत्वपूर्ण रूप से, इसने नोट किया कि अपीलकर्ता विभाग ने इस न्यायालय के समक्ष 427 दिनों की भारी देरी को माफ करने के लिए कोई उचित और ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया था।

5 (2011) 4 एससीसी 363। 6 (2012) 3 एससीसी 563।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

विभिन्न तिथियों का उल्लेख करते हुए। यह दावा अवैयक्तिक तंत्र और विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण किया गया था, जो आधुनिक तकनीकों के उपयोग और उपलब्ध होने को देखते हुए स्वीकार्य नहीं था। इसके अलावा, यह मानते हुए कि सीमा का कानून निस्संदेह सरकार सहित सभी को बाध्य करता है, इस न्यायालय ने माफी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

21. यह न्यायालय ईशा भट्टाचार्य बनाम रघुनाथपुर नफ़र अकादमी की प्रबंध समिति और अन्य मामलों में है। 7, विभिन्न का उल्लेख करते हुए

पूर्ववर्ती ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को चुनौती देने में प्रतिवादी/प्रबंधन समिति द्वारा उठाए गए ज्ञान की कमी और न्याय की विफलता की याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद इसने प्रामाणिक आदेश की कमी के आधार पर उक्त अंतरिम आदेश

को चुनौती देने में 2449 दिनों की देरी को माफ करते हुए विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया। निर्णय के पैराग्राफ 21 में वे सिद्धांत शामिल हैं जो इस न्यायालय द्वारा प्रक्रिया में विचार किए गए कई उदाहरणों से निकाले गए हैं।

22. मणिपुर राज्य में इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ और अन्य।कोटिंग लमकांग 8 को राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी पहली अपील को प्राथमिकता देने में 312 दिनों की देरी का सामना करना पड़ा। इस न्यायालय ने जनहित, सरकारों की अवैयक्तिक प्रकृति और राज्य के हित पर व्यक्तिगत त्रुटियों के प्रभाव के आधार पर, 5 करोड़ रुपये की लागत के भुगतान पर पहली अपील में देरी को माफ कर दिया। 50, 000/-।

23. दिल्ली विश्वविद्यालय (उपरोक्त) में, इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने में अपीलार्थी द्वारा 916 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया। यह न्यायालय, एम. एस. टी. को अलग करते हुए। तथ्यों पर कटीजी (ऊपर) ने कहा कि क्षमा करने पर विचार केवल एक उचित स्पष्टीकरण की प्रस्तुति पर किया जा सकता है, और ऐसा केवल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें अपीलकर्ता एक सार्वजनिक निकाय था। इसके बाद इसने विलंब का प्रदर्शन करने में अपीलार्थी के आचरण पर ध्यान दिया और न केवल अपील में, बल्कि पहली बार में उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिका को भी शामिल किया। अपीलार्थी के विलंब को क्षमा करने से इनकार करते हुए, यह विशेष रूप से था

7 (2013) 12 एससीसी 649। 8 (2019) 10 एससीसी 408।

शीओ राज सिंह (निर्णय) एलआरएस के माध्यम से।

753

& ओआरएस। V. भारत संघ और ए. एन. आर. [दीपांकर दत्त, जे.] 754

इस बात पर ध्यान दिया कि उस स्तर पर देरी को माफ करना जनहित के लिए प्रतिकूल होगा क्योंकि इसमें उत्तरदाताओं में से एक (दिल्ली मेट्रो रेल निगम) को विचाराधीन भूमि पर विकास करने के लिए वर्षों पहले बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था।

24. हम वर्तमान निर्णय के उद्देश्य से इस न्यायालय के कुछ अन्य निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं।

25. जी. रामगौड़ा बनाम विशेष। भूमि अधिग्रहण अधिकारी 9, जबकि

'पर्याप्त कारण' पर कानून की स्थिति का सारांश देते हुए, यह अवलोकन करने का अवसर मिला कि इस न्यायालय की कई घोषणाओं में लिंग अपीलों में देरी को माफ करने के मामले में अदालतों के विवेकाधिकार के क्षेत्र की रूपरेखा निर्धारित की गई है। यह सच पाया गया कि पक्ष को उसकी सलाह की सभी गलतियों से बचाने का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। यह देखते हुए कि पक्ष या उसके वकील की ओर से लापरवाही, जानबूझकर या घोर निष्क्रियता या निष्पक्षता की कमी होने पर विरोधी पक्ष को समयबद्ध अपील के संपर्क में आने का कोई कारण नहीं है, यह आगे कहा गया कि प्रत्येक मामले को अपने विशेष तथ्यों की विशिष्टताओं पर विचार करना होगा। हालाँकि, इस

न्यायालय ने दोहराया कि धारा 5 में 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति को एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके और आम तौर पर अपीलों को प्राथमिकता देने में देरी को न्याय के हित में माफ करने की आवश्यकता है, जहां देरी की माफी की मांग करने वाले पक्ष के लिए कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता या वास्तविक अधिकार की कमी आरोप योग्य नहीं है। इसके बाद ये शब्द आए:

“15. जिन मुकदमों में सरकार एक पक्ष है, उनमें एक और पहलू है जिसे शायद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि सरकार द्वारा की गई अपीलें इस तरह के चूक के लिए खो जाती हैं, तो किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं किया जाता है; लेकिन अंतिम विश्लेषण में, जनता का हित क्या है। सरकार के निर्णय सामूहिक और संस्थागत निर्णय होते हैं और निजी व्यक्तियों के निर्णयों की विशेषताओं को साझा नहीं करते हैं।***

17. इसलिए, यह आकलन करने में कि किसी विशेष मामले में, धारा 5 के प्रयोजनों के लिए 'पर्याप्त कारण' क्या है, शायद, उन विचारों से बाहर करना कुछ हद तक अवास्तविक हो सकता है जो इस मामले में जाते हैं।

9 (1988) 2 एससीसी 142।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

न्यायिक निर्णय, ये कारक जो सरकार के कामकाज के लिए विशिष्ट और विशिष्ट हैं। सरकारी निर्णयों को बनाने की प्रक्रिया में काफी हद तक प्रक्रियात्मक लालफीताशाही के कारण आम तौर पर धीमी गति से लिया जाता है। इसलिए, अक्षांश की एक निश्चित मात्रा की अनुमति नहीं है। यह सही कहा गया है कि जो लोग सरकार की जिम्मेदारी लेते हैं, उन्हें 'जोड़ों पर थोड़ा खेल' होना चाहिए। यदि न्यायिक दृष्टिकोण को अवास्तविक नहीं बनाया जाना है तो सरकारी कामकाज पर इन सीमाओं की उचित मान्यता-निश्चित रूप से, उचित सीमाओं के भीतर-आवश्यक है। ऐसे मामलों में सरकारी और निजी पक्षों को सभी मामलों में एक ही आधार पर रखना शायद अनुचित और अवास्तविक होगा। सरकारी कामकाज की प्रकृति में निहित निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए आकस्मिक प्रक्रियात्मक देरी है।”
[...]

26. एमएस. कटीजी (उपरोक्त) को भी तीन माननीयों की एक पीठ ने देखा था।

हरियाणा राज्य बनाम चंद्र मणि **10** में इस न्यायालय के न्यायाधीश जहां हम

और निम्नलिखित चर्चा: “11. *** जब राज्य एक आवेदक होता है, जो विलंब की क्षमा के लिए प्रार्थना करता है, तो यह सामान्य ज्ञान है कि अवैयक्तिक तंत्र और विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण, जो नोट बनाने, ले-पुशिंग और पास-ऑन-द-बक लोकाचार से ओत-प्रोत है, राज्य की ओर से देरी को समझना कम कठिन पंथ है, हालांकि अनुमोदन करने के लिए अधिक कठिन पंथ है, लेकिन राज्य समुदाय के सामूहिक कारण का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वयंसिद्ध है कि

अधिकारी/अभिकरणों द्वारा निर्णय आमतौर पर धीमी गति से लिए जाते हैं और इसे एक मेज से दूसरी मेज पर धकेलने और इसे काफी समय तक मेज पर रखने की प्रक्रिया के कारण देरी-जानबूझकर या अन्यथा-एक दिनचर्या है। उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक लाल-टेप की काफी देरी एक सामान्य विशेषता है। इसलिए, अक्षांश की निश्चित मात्रा अस्वीकार्य नहीं है। यदि राज्य द्वारा की गई अपीलें इस तरह की चूक के लिए खो जाती हैं तो किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं किया जाता है, लेकिन अंतिम विश्लेषण में जो पर्याप्त है, वह जनहित है। इसलिए, 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति को न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण में व्यावहारिकता के साथ माना जाना चाहिए, न कि प्रत्येक को समझाने के लिए पर्याप्त कारण का तकनीकी पता लगाना चाहिए।

10 (1996) 3 एससीसी 132।

शीओ राज सिंह (निर्णय) एलआरएस के माध्यम से।

755

& ओआरएस। V. यूनियन ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर. [दीपांकर दत्त, जे.] 756

दिन का विलंब। सरकारी स्थितियों के कार्यकरण के लिए विशिष्ट और विशिष्ट कारक न्याय-उन्मुख प्रक्रिया में व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए संज्ञानात्मक होंगे और इसकी आवश्यकता होगी।” ***

27. यह न्यायालय, विशेष तहसीलदार, भूमि अधिग्रहण बनाम के. वी.

आयसुम 11 ने यह देखने का अवसर प्राप्त किया कि राज्य के लिए इसकी क्षमा की मांग करते समय देरी का दैनिक स्पष्टीकरण प्रदान करना आवश्यक नहीं होगा। उसमें प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: “अब यह तय कानून है कि जब सरकार के कहने पर देरी की गई थी, तो दिन-प्रतिदिन की देरी की व्याख्या करना बहुत मुश्किल होगा। सरकार के कामकाज का लेन-देन अधिकारियों द्वारा आराम से किया जा रहा था, जिनका अलग-अलग स्तरों पर कोई व्यक्तिगत हित नहीं था या जिनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं था। मामलों को तेजी से निपटाने में कोई भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं लेता है। वास्तव में कई चरणों में, वे किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अपना समय लेते हैं। देरी की ओर इशारा करने के बावजूद, वे अपील में अंतिम निर्णय के लिए त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं। यह मामला ऐसे ही मामलों में से एक है। यह सच है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 में अदालत की संतुष्टि के लिए देरी के स्पष्टीकरण की परिकल्पना की गई है और सीमा अधिनियम के मामलों में राज्य और नागरिक के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। फिर भी सबूत के सख्त मानक को अपनाने से सार्वजनिक न्याय की गंभीर विफलता होती है। इसके परिणामस्वरूप अपील दायर करने की प्रक्रिया में देरी के कुशल प्रबंधन द्वारा सार्वजनिक शरारत होगी। न्यायालय का दृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिए लेकिन पांडित्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। उन परिस्थितियों में, अधीनस्थ न्यायाधीश ने सही दृष्टिकोण अपनाया है और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में समीक्षा आवेदन में हर दिन की देरी को समझाने पर जोर दिए बिना देरी को माफ कर दिया है। उच्च न्यायालय आदेश को रद्द करने में सही नहीं था। देरी को उचित रूप से माफ कर दिया गया।”

विश्लेषण

28. हमने अपीलार्थियों और प्रत्यर्थियों की ओर से क्रमशः श्री शर्मा और श्री सेन को पेश होते हुए सुना है और चुनौती के तहत आदेश का अध्ययन किया है।

11 (1996) 10 एससीसी 634।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

29. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, कोई विवाद नहीं हो सकता है कि इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि निजी पक्षों और राज्य के मूल अधिकार केवल देरी के तकनीकी विचारों के कारण दहलीज पर पराजित न हों। हालाँकि, इन निर्णयों के बावजूद, हम दोहराते हैं कि अदालतों के लिए उपलब्ध एक विवेकाधीन शक्ति होने के नाते, विवेकाधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से दिखाए गए कारण की पर्याप्तता और स्पष्टीकरण की स्वीकार्यता की डिग्री पर निर्भर करना चाहिए, देरी की अवधि मायने नहीं रखती है। कभी-कभी, पर्याप्त कारण दिखाए जाने की कमी या एक स्वीकार्य स्पष्टीकरण दिए जाने के कारण, सबसे छोटी सीमा की देरी को माफ नहीं किया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य मामलों में, लंबी अवधि की देरी को माफ किया जा सकता है यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक और स्वीकार्य है। बेशक, अदालतों को एक 'स्पष्टीकरण' और एक 'बहाने' के बीच अंतर करना चाहिए। एक 'स्पष्टीकरण' किसी को सभी तथ्य देने और किसी चीज़ का कारण निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। यह किसी विशेष घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में मदद करता है और व्यक्ति को यह इंगित करने की अनुमति देता है कि जो कुछ हुआ है वह उसकी गलती नहीं है, अगर यह वास्तव में उसकी गलती नहीं है। हालाँकि, एक 'स्पष्टीकरण' को एक 'बहाना' से अलग करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए। हालाँकि लोग 'स्पष्टीकरण' और 'बहाना' को एक ही चीज़ के रूप में देखते हैं और दोनों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन एक अंतर है जो वास्तविक होने के बावजूद वास्तविक है। एक 'बहाना' अक्सर एक व्यक्ति द्वारा हमले के दौरान जिम्मेदारी और परिणामों से इनकार करने के लिए किया जाता है। यह एक तरह की रक्षात्मक कार्रवाई है। किसी चीज़ को सिर्फ एक 'बहाना' कहने का मतलब यह होगा कि जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह सच नहीं माना जाता है। इस प्रकार कहा गया है कि ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो सभी स्थितियों को पूरा करता है और इसलिए, पर्याप्त कारण के अस्तित्व या अनुपस्थिति के आधार पर देरी की माफी के लिए प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों पर तय करना पड़ता है। इस स्तर पर, हम इस बात पर अफसोस जताते हैं कि यह केवल बहाने हैं, न कि स्पष्टीकरण, जिन्हें अक्सर उन छिपी हुई ताकतों से सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए लंबी देरी को माफ करने के लिए स्वीकार किया जाता है, जिनका एकमात्र एजेंडा यह सुनिश्चित करना है कि एक योग्य दावा निर्णय के लिए उच्च न्यायालयों तक न पहुंचे।³⁰ जो भी हो, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम देरी की माफी के लिए एक आवेदन पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि देरी की माफी के लिए अनुरोध को मंजूरी देने वाले उच्च न्यायालय के विवेकाधीन आदेश पर अपील कर रहे हैं। पहले वाले के मामले में, माफी देना है या नहीं, यह एकमात्र सवाल होगा, जबकि बाद वाले में, माफी के लिए प्रार्थना के अनुदान के पक्ष में

विवेक का उचित प्रयोग किया गया है या नहीं, यह सवाल होगा। कानून काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि "अपील की अदालत 757

शीओ राज सिंह (निर्णय) एलआरएस के माध्यम से।

& ओआरएस। V. यूनियन ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर. [दीपांकर दत्त, जे.] 758

सामान्य रूप से निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि किसी प्राधिकरण की आवश्यकता है, तो हम स्पष्ट रूप से निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं

मंजूनाथ आनंदप्पा बनाम तमन्नासा **12** में, जो बदले में गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड बनाम गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड में निर्णय पर निर्भर था। गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर

सभा **13** जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "एक अपीलीय शक्ति तब हस्तक्षेप नहीं करती है जब अपील किया गया आदेश सही नहीं होता है, बल्कि केवल तब होता है जब यह स्पष्ट रूप से गलत होता है।"

31. इस अपील में चुनौती के तहत आदेश 21 दिसंबर 2011 का है। यह उस समय प्रस्तुत किया गया था जब एमएसटी में निर्णय लिए गए थे। काटीजी

(सुप्रा), रामगौड़ा (सुप्रा), चंद्र मणि (सुप्रा), के. वी. आयसुम्मा

(सुप्रा) और लिपोक एओ (सुप्रा) फाई एल्ड पकड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि उक्त निर्णय अब अंतिम नहीं हैं, क्योंकि बाद के किसी भी निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है। हालाँकि हाल के दिनों में कुछ निर्णय लिए गए हैं [एम. पी. बनाम राज्य। भेरूलाल 14 दिल्ली विश्वविद्यालय (उपरोक्त) के अलावा एक ऐसा निर्णय है जिसने समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में सरकारी सुस्ती, विलंब और आलस्य को देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया है, फिर भी, उच्च न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग को उपरोक्त निर्णयों में बताए गए उदार और न्याय उन्मुख दृष्टिकोण के आधार पर परखा जाना चाहिए, जिन्हें ऊपर संदर्भित किया गया है। हम मानते हैं कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के समर्थन में निम्नलिखित कारण दिए हैं:

ए। सीमा कानून की स्थापना सार्वजनिक नीति पर की गई थी, और यह कि एक वादी की ओर से कुछ चूक, अपने आप में, देरी की माफी से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी क्योंकि यह न्याय की विफलता का कारण बन सकता है।

बी। पर्याप्त कारण अभिव्यक्ति अदालतों के लिए पर्याप्त न्याय करने के लिए पर्याप्त लोचदार है। इसके अलावा, जब एक दूसरे के खिलाफ पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचार रखे जाते हैं, तो पहला प्रबल होता है।

ग. यह अदालतों पर है कि वे देरी के लिए दिखाए गए कारण की पर्याप्तता पर विचार करें, और यदि देरी ठीक से की जाती है तो ऐसे मामलों में विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय देरी की अवधि हमेशा निर्णायक नहीं होती है।

12 (2003) 10 एससीसी 390। 13 (1980) 2 एससीसी 593। 14 (2020) 10 एससीसी 654।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

समझाया। इसके अलावा, देरी को माफ करने के लिए ऐसे आवेदनों पर निर्णय लेते समय दावे के गुण-दोष पर भी विचार किया जाना था।

घ. इसके अलावा, अत्यधिक अस्पष्टीकृत देरी और समझाई गई देरी के बीच अंतर किया जाना चाहिए, जहां वर्तमान मामले में, प्रथम प्रतिवादी ने संदर्भ न्यायालय के समक्ष सरकारी अधिकारियों और सरकारी वकील की ओर से लापरवाही के कारण देरी को पर्याप्त रूप से समझाया था।

ई. लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी राज्य के माध्यम से सार्वजनिक हित के बजाय पर्याप्त रूप से उत्तरदायी होगा। उच्च न्यायालय ने एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए इच्छुक महसूस किया क्योंकि इसमें लापरवाही निर्दयता पर सीमित नहीं थी।

32. इन कारणों को देखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से विवेकाधिकार का प्रयोग किए जाने पर विचार नहीं करते हैं। चुनौती के तहत आदेश को स्पष्ट रूप से गलत आदेश होना चाहिए ताकि हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी हो, जो कि नहीं है।

33. अब उन दो निर्णयों में अंतर करने का समय आ गया है जिन पर श्री शर्मा बहुत अधिक निर्भर थे।

34. बलवंत सिंह (ऊपर) का जन्म मकान मालिक-किरायेदार विवाद से हुआ था। हमारी विचार प्रक्रिया को उस कानून द्वारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं है जो इस बात पर निर्धारित है कि केंद्र सरकार एक पक्ष होने के मामले में निजी पक्षों के बीच विवाद में 'पर्याप्त कारण' क्या होगा।

35. श्री शर्मा के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय (उपरोक्त) एक बड़ी पीठ का निर्णय है और इसलिए यह हम पर बाध्यकारी है। दिल्ली विश्वविद्यालय (उपरोक्त) का निर्णय लेते समय इस न्यायालय को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा कि भले ही देरी को माफ कर दिया जाए, लेकिन यह अपीलार्थी विश्वविद्यालय के आकस्मिक दृष्टिकोण के कारण प्रतिवादी दिल्ली मेट्रो रेल निगम के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा। यह न्यायालय, अपील को मंजूरी देने के लिए कुलपति की अनुपलब्धता और मामले में सामने रखे गए अन्य कारणों के तर्क पर, यह निष्कर्ष नहीं निकाल सका कि देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण पूरा किया गया था; इसलिए, देरी को माफ करने से इनकार कर दिया गया। निर्णय वास्तव में इस न्यायालय के समक्ष निहित पूर्वाग्रह कारक के कारण तथ्यों को बदल देता है।

& ओआरएस। V. यूनियन ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर. [दीपांकर दत्त, जे.] 760

36. हम श्री सेन द्वारा उद्धृत कोटिंग लमकांग (ऊपर) का भी उल्लेख कर सकते हैं, जहां इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की उसी पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय (ऊपर) का निर्णय लिया था, जिसका विचार था कि राज्य के कामकाज की अवैयक्तिक प्रकृति को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, जबकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत चूक को सामूहिक हित की कीमत पर नहीं चुना जाए। संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

“7. लेकिन ऊपर के रूप में निष्कर्ष निकालते समय, न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि वह नौकरशाही देरी और सरकारी निर्णय तक पहुंचने में धीमी गति और यह तय करने के नियमित तरीके के बारे में भी सचेत रहे कि क्या राज्य को अपने प्रतिकूल निर्णय के खिलाफ अपील करना चाहिए। यह देखते हुए भी कि सीमा का कानून पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित करेगा, न्यायालय ने महसूस किया कि राज्य के नेतृत्व में अपील में देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए।

8. ऐसी ही परिस्थितियों में सरकार के कामकाज की अवैयक्तिक प्रकृति का ध्यान रखा जाना चाहिए जहां व्यक्तिगत अधिकारी जिम्मेदारी से कार्य करने में विफल हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य के संस्थागत हितों के साथ अन्याय होगा। यदि राज्य के नेतृत्व में अपील व्यक्तिगत चूक के लिए खो जाती है, तो जो दोषी हैं, उन्हें आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।”

(हमारा उल्लेख करते हुए, जोर देने के लिए) 37। प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर गंभीरता से विचार करने के बाद, हम महसूस करते हैं कि उच्च न्यायालय का समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण देरी को माफ करने का निर्णय, उसमें दिए गए कारणों के लिए, हस्तक्षेप की गारंटी देने वाली किसी भी त्रुटि के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसा कि उपरोक्त निर्णयों से पता चलता है, विवेक का ऐसा प्रयोग, कभी-कभी, न्यायालयों द्वारा एक उदार और न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण की मांग करता है, जहां राज्य को कुछ छूट प्रदान की जा सकती है। राज्य द्वारा किसी अपील को निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने से रोकने के लिए काम करने वाली छिपी हुई शक्तियों को शायद ही नजरअंदाज किया जा सकता है ताकि उच्च न्यायालय को निचली अदालत के आदेश की वैधता और वैधता पर निर्णय देने की अनुमति न दी जा सके और इस तरह अपवित्र लाभ प्राप्त हो सकें। प्रतिस्पर्धी हितों के संतुलन पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर सरकारी कार्यों की भव्य योजना के काम करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

निष्कर्ष

38. पूर्वगामी कारणों और यहाँ प्राप्त विशेष परिस्थितियों के लिए कि विवादित आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम प्रतिवादी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को यथोचित रूप से माफ करता है, वर्तमान अपील, तदनुसार, खारिज कर दी जाती है।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

39. दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन